what is the state of progress and what is the latest position on linking of rivers so that the distribution of water may be more equitable.

MR. SPEAKER: That does not arise out of this Question.

SHRI V. ARUNACHALAM: I understand that there are some forces which are trying to utilise water against the terms and conditions of the Agreement which has been reached between the two States. I want to have a categorical assurance from the hon. Minister in this regard. Will the Government come forward to give the assurance that the scheme will be implemented without any diversion or deviation from the conditions of the Agreement which has been reached?

SHRI SURJIT SINGH BARNALA: The Agreement has been reached between the States, and that has to be honoured in that very form.

Decentralisation of DDA

*189. SHRI M. RAM GOPAL REDDY: Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) whether there is a proposal to decentralise DDA; and

(b) if so, the details thereof?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम किंकर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नही उठता।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : प्रश्न क्यों नहीं उठता है, प्रश्न उठता है क्योंकि अगर इस का डिसेण्ट्रेलाइजेशन नहीं करेंगे तो इस पर जो 1 करोड़ 50 लाख रुपया हर महीने इस्टाबिलिशमेंट पर खर्च हो रहा है, वह होता रहेगा। मै मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि डिसेण्ट्रेलाइजेशन करने से इस मे कुछ खर्च कम होगा और काम इफीशियेंटली चलेगा या नही ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : यह आप की तजवीज है, सवाल नहीं है लेकिन मै आप से यह अर्ज कर दूं कि जहा तक इस के कार्य को स्ट्रीमलाइन करने का ताल्लुक है, एक आफिशियल कमेटी बनाई गई है, जो इन तीन, चार चीजो पर गौर कर रही है :

(1) To make an over-all assessment of the functioning and activities of the DDA.

(2) To examine how far the Authority has been able to meet the objectives for which it was set up; and

(3) To assess the relationship of the Authority with other external agencies such as Delhi Administration, Municipal Corporation of Delhi etc.

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : इस को डीसेंट्रलाइज करने से ज्यादा फ़ायदे होंगे, क्योंकि सुपरविज़न मे भी आसानी हो जायेगी। क्या मंत्री महोदय इस पर पुनः विचार करेंगे ?

श्री सिकन्दर बख्त : आनरेबल मेम्बर अपनी तजवीजें हमे लिख कर भेज दें। हम उन्हें देख लेंगे।

SHRI MOHD. SHAFI QURESHI: The Hon. Minister has stated that he has formed a Committee to go into

the whole gamut of D.D.A.'s functioning. May I know which other Ministries are involved in that Committee and when the Report of the Committee will be submitted to the Government?

SHRI SIKANDAR BAKHT: The Report of the Committee was due to be submitted on 28th February but they have asked for an extension of three months.

SHRI MOHD. SHAFI QURESHI: Which are the other Ministries that are involved?

SHRI SIKANDAR BAKHT: No other Ministry is involved: it is the local Administration the Municipal Corporation of Delhi, the New Delhi Municipal Committee, L & D etc that are involved

श्री विजय कुमार मल्होत्रा : मंत्री महोदय ने बताया है कि डी० डी० ए० के बारे में जो कमेटी बनाई गई है, उसमें सिर्फ आफिशल्ज को रखा गया है । क्या कोई ऐसी तजवीज नहीं है कि जिन नान-आफिशल्ज का ताल्लुक डी० डी० ए० की वर्किंग से है, उन्हें और दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, कार्पोरेशन आदि के इलेक्टिड रिप्रेजेन्टेटिव्ज को भी ऐसी कमेटीज के साथ एसोशिएट किया जाये, ताकि इन की रिपोर्ट्स केवल आफिशल वर्शन बन कर न रह जायें, बल्कि इन की तरफ से ठीक रिपोर्ट्स दी जाय ?

श्री सिकन्दर बख्त : अध्यक्ष महोदय, अगर यह बात इस सवाल से पैदा होती है, तो मैं कुछ अर्ज कर दूं । इट डज नाट फालो फ्राम दिस कवेश्चन एट आल ।

श्री किशोर लाल : इस से पहले भी पिछले पांच साल में डी० डी० ए० के वर्किंग के मुताल्लिक तीन कमेटियां बन चुकी है और वे अपनी रिपोर्ट्स भी सबमिट कर चुकी है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या किसी मंत्री या मंत्रालय ने उन रिपोर्ट्स को देखा है और उन्हें पढ़ने के बाद इस नई कमेटी को मुकर्रर करने की जरूरत महसूस हुई है, या उन्हें पढ़ा ही नहीं गया है और फिर एक कमेटी मुकर्रर कर दी गई है और जैसा हाल उन कमेटियों की रिपोर्ट्स का हुआ है, वैसा ही हाल इस रिपोर्ट का भी होगा ?

श्री सिकन्दर बख्त : यह कमेटी बुनियादी तौर पर इस बात को जहन में रख कर बनाई गई है कि दिल्ली में मल्टी-प्लिसिटी आफ एथारिटीज है । आनरेबल मेम्बर का रफरेंस कौन सी कमेटी की तरफ है, यह मेरे लिए समझना मुश्किल है ।

Policy for Appointment of Chief Executives to State Farms Corporation and National Seeds Corporation

*190. SHRI BIRENDRA PRASAD: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to lay a statement showing.

(a) whether Government's Policy is to appoint the Chief Executives in the State Farms Corporation of India and National Seeds Corporation only out of the persons who are either at the verge of retirement or re-employed after retirement;

(b) if so, will it not affect the employment potential of the younger generation who may be competent to hold these posts,

(c) have such posts ever been circulated to the Bureau of Public Enterprises before the appointment to these posts are made; and

(d) what is the policy of Government for recruitment to these top and lower posts in these two organisations